भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 269

जिसका उत्तर 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

14 माघ, 1942 (शक)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

269. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पारिस्थितिकी प्रौद्योगिक कायाकल्प हेतु समाज के सभी पहलुओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को तैनात करने के लिए तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर देश के शासन में उपयोग किए जा रहे एआई सिस्टम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा समाज में एआई के समेकन हेतु क्या नीति लागू की गई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) : एआई एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें मशीन लर्निंग (एमएल) और डीप लर्निंग (डीएल) शामिल है जिसमें स्वत: ही जटिल एल्गोरियम और विशेषीकृत हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर सॉल्यूशन शामिल है। एआई ईकोसिस्टम की प्रकृति उभरती हुई है। एआई और संबंधित प्रौद्योगिकियों के अभिनव प्रस्तावों के कारण भारतीय आईटी/आईटीईएस और स्टार्ट अप कंपनियों ने इनमें भारी मात्रा में निवेश किया है। समाज में विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशनों और अन्य आईटी प्लेटफॉर्मों के जरिए एआई आधारित सॉल्यूशनों का उपयोग किया जा रहा है जबकि इसके बारे में लोगों को स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं है।

(ख) : एआई प्रणालियों का उपयोग कर रही कुछ बड़ी सरकारी पहलें हैं-नेशनल लैंग्वेज ट्रांस्लेशन मिशन (क्षेत्र-मल्टी-डिसिप्लिनरी), माइगव साथी बॉट और मायगव कोरोना हैल्पडेस्क (स्वास्थ्य देख-रेख पर प्रमुख फ़ोकस के साथ क्षेत्र -मल्टी-डिसिप्लिनरी), स्मार्ट सिटीज़ मिशन (क्षेत्र-शहरी विकास), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (क्षेत्र-कौशल विकास), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल नवोद्भव मिशन, आयुष्मान भारत (क्षेत्र-स्वास्थ्य देख-रेख), सरकारी ई-बाज़ार स्थल (क्षेत्र-खरीद), फेसलैस कर निर्धारण (क्षेत्र-वित्त) इत्यादि।

(ग) : भारत सरकार ई-शासन स्पेस में एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की दिशा में कटिबद्ध है। एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति वर्ष 2018 में प्रकाशित की गई है। इस नीति के अनुसार राष्ट्रीय एआई पोर्टल को मई 2020 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य उद्योग, शैक्षणिक जगत और सिविल सोसायटी के सहयोग से एआई सम्बंधित विकासों के बारे में सूचना प्रदान करनी है।

****